

कोलकाता, समाज :
मुर्शिदाबाद जिले में हाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान एक विशेष समुदाय के लोगों पर कथित अत्याचार के खिलाफ तख्तियां लेकर भाजपा विधायकों ने बुधवार को राज्य विधानसभा के निकट 'हिंदू शहीद दिवस' मनाया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने उन पिता-पुत्र के लिए भी न्याय की मांग की जिनकी पिछले सप्ताह मुस्लिम बहुल जिले में हिंसा के दौरान भीड़ ने हत्या कर दी थी। इस दिन, विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा के लगभग 40 विधायकों ने

सिमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और केंद्रीय एजेंसियों को दोषी ठहरा रही है, लेकिन वास्तव में उनकी पुलिस और प्रशासन हिंदुओं की रक्षा करने में विफल रहा तथा उत्पात जारी रहने दिया। दूसरी ओर, यह सीमा सुरक्षा बल ही था जिसने हस्तक्षेप किया और हालात को बिगड़ने से रोका। उन्हें (ममता) सच बोलने का साहस दिखाना चाहिए।

□ शुभेंद्र ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी से की बंगाल आने की अपील

वहीं, दूसरी ओर, शुभेंद्र अधिकारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बंगाल आने की अपील की। उन्होंने कहा कि बंगाल को यूपी की तरह ठीक करने की जरूरत है। वहीं, ममता ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा 'सबसे बड़ा भोगी' कह दिया। शुभेंद्र अधिकारी ने तुणमूल पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पूर्व नियोजित थी।

‘आश्वस्त नहीं’, उ

□ केंद्रीय मंत्री ने पुलिस महानिदेशक से मिलने के लिए दो से अधिक समय तक मुर्शिदाबाद के बेघरों के साथ भवानी भवन के बाहर दिया धरना

कोलकाता, समाजा : भाजपा नेता मुर्शिदाबाद के बेघर लोगों के साथ बुधवार को राज्य पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार से मुलाकात की मांग पर भवानी भवन के सामने धरने पर बैठ गए। दो घंटे से अधिक समय तक धरने के बाद वे अंततः राजीव कुमार से मिलने में सफल हुए। हालांकि, सुकांत मजूमदार इस मुलाकात से बहुत खुश नहीं है। बता दें कि वक्फ मंडू में अर्शात के कारण मुर्शिदाबाद में कई लोग बेघर हैं। इस दिन, सुकांत उनमें से कुछ के साथ भवानी भवन गये। बताया गया कि मुर्शिदाबाद में घटना के बाद राज्य के डीजीपी ने

न की आशंका

करने के बाद जब पीड़ित नौकरी जॉइन करने पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र पूरी तरह से नकली हैं। संबंधित स्थानों में स्मृष्ट रूप से बताया कि ऐसे किसी भी नियुक्ति की जानकारी उनके पास नहीं है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अधिकारियों का मानना है कि इस जालसाजी का दायरा और भी बड़ा हो सकता है और आने वाले दिनों में अधिक शिकायतें सामने आ सकती हैं। फिलहाल पुलिस आपरों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

बेगमपुर इलाके में बुधवार सुबह एक सनसनीखेज और विचित्र घटना सामने आई। स्थानीय लोगों ने एक कुत्ते को इसान का कटा हुआ सिर मुंह में लेकर घूमते हुए देखा, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

घटना सुबह करीब 9 बजे की है, जब चंडीताल के बेगमपुर 20 नंबर रेलगाड़ी के पास स्थित एक बगीचे में लोगों ने यह भयावह दृश्य देखा। घुरत ही स्थानीय लोगों ने कुत्ते को भगाया और पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही कामारकुंडुंजी जीआरपी और चंडीताल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मानव सिर को बरामद किया। घटनास्थल

तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुद्देश्वरी की के साथ मुठों को सुलझाने की इच्छा व्यक्त की। मानहानि के इस मुकदमे में गोखले को माफी मांगने और 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव पुरी ने समझौते के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पुरुषोत्तम कुमार कोरव ने पुरी और गोखले के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद गोखले की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें एक जुलाई, 2024 के फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया गया था। एक जुलाई 2024 को उच्च

न्यायालय में मानहानि के मुकदमे में गोखले को माफी मांगने और पुरी को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया था। गोखले के वकील ने आग्रह किया कि यदि वादी को नुकसान हुआ है तो अदालत उदार दृष्टिकोण अपना सकती है, इसकी भरपाई प्रतिवादी पर लागत लागू करी जा सकती है। उन्होंने अनुरोध किया कि 50 लाख रुपये के हर्जाने का आदेश वापस लिया जाए क्योंकि उनके मुवक्किल के पास धन की कमी है।

गोखले के वकील ने कहा कि आज उनके पास धन नहीं है, इसलिए यदि किसी भी राशि का भुगतान किए बिना किसी समझौते की संभावना है, तो मेरा मुवक्किल उस प्रस्ताव का लाभ उठाने के लिए तैयार है। हालांकि, पुरी ने समझौते के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उनके वकील ने दलील दी कि गोखले ने बिना किसी आधार के उनके खिलाफ 'झूठी' बयानबाजी की। पुरी ने 2021 में उच्च न्यायालय का रुख करते हुए दावा किया कि गोखले ने जिनैवा में उनके (पुरी के) स्वामित्व वाले एक अपार्टमेंट के संदर्भ में वित्तीय मामलों को लेकर आधारहीन और झूठे आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है।

समुदाय के धार्मिक नेताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस सुझाव का स्वागत किया जिसमें उन्होंने उन्हें वक्फ (संगोधन) अधिनियम पर अपनी आपत्तियां व्यक्त करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने का समय मांगने के लिए कहा था।

अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मौलाना मो. बक़ीबिल्लाह मोल्ला ने ममता की सलाह को 'सकारात्मक' बताया और कहा कि वे जल्द ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने के बारे में फैसला करने के लिए एक बैठक करेंगे। मोल्ला ने कहा कि हम जल्द ही इस मुद्दे पर एक बैठक करेंगे। हम लोगों से शांति बनाए रखने और कानून को अपने हाथ में नहीं लेने

नहीं देने की अपील भी करते हैं। फुफ्फूरा शरीफ के मौलवी पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद में किसी भी हिंदू पर हमला नहीं हुआ और उन्होंने भाजपा पर आम लोगों को प्रेरित करने और हिंसा भड़काने के लिए गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री के प्रस्तावों का स्वागत करते हैं और हम इस अधिनियम के खिलाफ लड़ेंगे। हावड़ा जिला इमाम फंड के अध्यक्ष शेख मोहम्मद अयूब अली ने कहा कि हम जल्द ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगने का फैसला करेंगे। हम आज की बैठक से खुश हैं और यह निश्चित रूप से वक्फ अधिनियम के खिलाफ लड़ाई में हमारी मदद करेगी।



कार्काई करने का अनुश्रवण करता हूं। सांसद ने कहा कि क्षेत्र में बचे लोगों की ओर से प्राप्त परेशान करने वाली रिपोर्टों और आरोपों के बारे में स्थायी समिति जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए तत्काल दौरा करे। उन्होंने कहा कि समिति का एक प्रतिनिधिमंडल समीक्षा करने के लिए मुर्शिदाबाद जाए ताकि वहां की वास्तविकता का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि समिति को राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुर्शिदाबाद के एसपी को भी बुलाना चाहिए ताकि अब तक की गई छानबीन के बारे में विस्तृत रिपोर्ट ली जा सके। खान ने कहा कि राज्य पुलिस से पूछा जाए कि प्रदेश में बार बार हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के दौरे से दवाओं के पीछे की सच्चाई का पता लगाने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि न्याय और पारदर्शिता बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि इस मामले में आपकान्तेतृत्व कानून के शासन में विश्वास बहाल करने और प्रभावित नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

न्यूज इन ब्रीफ

ईडी ने महादेव सट्टेबाजी मामले में कई राज्यों में छापे मारे

नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धनशोधन मामले में बुधवार को ‘ईजमाईट्रिप’ के संस्थापक निशांत पिट्टी के परिसरों सहित कई राज्यों में फिर से छापे मारे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, चेन्नई और ओडिशा के संबलपुर में स्थित परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं। छापे ऑनलाइन यात्रा बुकिंग मंच ‘ईजमाईट्रिप’ के संस्थापक और अध्यक्ष पिट्टी के परिसर पर भी मारे जा रहे हैं। यह मामला तब सामने आया जब संघीय जांच एजेंसी ने कुछ साल पहले दावा किया था कि कलिसाग के कई राजनेताओं और नौकरशाह ऐप से जुड़े अवैध संचालन और उसके बाद हुए मौद्रिक लेनदेन में कथित रूप से शामिल हैं। इस मामले में पहले भी छापे मारे जा चुके हैं। ईडी ने अतीत में आरोप लगाया था कि ‘महादेव ऑनलाइन बेटिंग’ (एमओबी) गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप के संबंध में उसकी जांच में छत्तीसगढ़ के विभिन्न उच्च पदस्थ राजनेताओं और नौकरशाहों की संलिप्तता सामने आई है। इस ऐप के दो मुख्य प्रवर्तक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल इसी राज्य से हैं।

जेपी नट्टा ने अमित शाह से मुलाकात की

नयी दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नट्टा ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। नट्टा पिछले हफ्ते पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की थी। इन बैठकों के एजेंडे के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रक्षा मंत्री राजीव सिंह और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने मंगलवार रात भाजपा अध्यक्ष के आवास पर बैठक की थी। पार्टी सूत्रों ने कहा कि वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री अक्सर सामयिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सामाहिक बैठक करते हैं। भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन से पहले कई प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। नट्टा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं। नए अध्यक्ष के चुनाव तक वह पार्टी प्रमुख के पद पर हैं।

ईडी ने “अवैध” दस्तावेज तैयार करने वाले बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया

नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने कोलकाता में एक बांग्लादेशी नागरिक को अपने देश के नागरिकों के लिए “अवैध” भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड तैयार करने में भूमिका के लिए धन शोधन निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया है। ईडी ने एक बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल में सात परिसरों में तलाशी के बाद मंगलवार को आजाद मलिक उर्फ अहमद हुसैन आजाद को हिरासत में लिया गया। ईडी ने बयान में कहा कि कोलकाता में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने मलिक को 13 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। धन शोधन का मामला मलिक के खिलाफ स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। उसके खिलाफ 1946 के विदेशी अधिनियम के तहत “व्यथ दस्ता-वेजों के बिना” भारत में रहने और धन के बदले अवैध प्रवासियों के लिए “धोखाधड़ी” के माध्यम से भारतीय पासपोर्ट और अन्य दस्ता-वेज बनाने में “संलिप्तता” को लेकर मामला दर्ज किया गया था।

दिल्ली सरकार 23 अप्रैल से 1,000 से अधिक स्थानों पर संस्कृत भाषा की नि:शुल्क कक्षाएं आयोजित करेगी

नयी दिल्ली : दिल्ली में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार यहां के विद्यालयों, कॉलेजों और मंदिरों सहित 1,000 से अधिक स्थानों पर संस्कृत की 10 दिवसीय नि:शुल्क कक्षाएं आयोजित करेगी। संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को यह घोषणा की। योजना के अनुसार, संस्कृत भाषा की कक्षाएं 23 अप्रैल से शुरू होंगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में शिविर आयोजित करने के लिए एनजीओ ‘संस्कृत भारती’ के साथ साझेदारी की है।

दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई में केवल कांग्रेस ही आरएसएस-भाजपा को हरा सकती है: राहुल



की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने का संकल्प व्यक्त किया। गांधी गुजरात में संगठन को नया रूप देने के कांग्रेस के प्रयासों के तहत जिला इकाइयों को

मुंबई हवाई अड्डे पर 21.78 करोड़ रुपये की कोकीन तस्करी में शामिल गिनी की एक महिला गिरफ्तार

मुंबई : राजस्व आसूचना निद-ेशालय (डीआरआई) ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 21.78 करोड़ रुपये मूल्य की कोकीन की तस्करी के आरोप में अफ्रीकी देश गिनी की एक महिला को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि महिला केन्या की राजधानी नैरोबी से यहां छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी थी। उन्होंने कहा, विशिष्ट सूचना के आधार पर डीअ-रआई की मुंबई जोनल इकाई की एक टीम ने महिला यात्री को हवाई अड्डे पर रोका। उसकी तलाशी ली

ईडी ने रॉबर्ट वाद्रा से लगातार दूसरे दिन पांच घंटे पूछताछ की, बृहस्पतिवार को फिर तलब किया

■ ईडी जल्द ही रॉबर्ट वाद्रा के खिलाफ धनशोधन के तीन मामलों में आरोप-पत्र दाखिल कर सकती हैं: सूत्र

नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कारोबारी एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाद्रा से 2008 के हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े कथित धनशोधन मामले में उनसे लगातार दूसरे दिन करीब पांच घंटे पूछताछ की। एजेंसी ने उन्हें बृहस्पतिवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। वाद्रा ने ईडी की कार्रवाई

अदालत ने एमयूडीए मामले में सीबीआई जांच को लेकर अर्जी पर सिद्धरमैया, उनकी पत्नी को नोटिस जारी किया

बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एमयूडीए भूखंड आवंटन मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने के अनुरोध संबंधी सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की एक अर्जी पर बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उनकी पत्नी और अन्य को नोटिस जारी किया। सिद्धरमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा उनकी पत्नी पार्वती बी एम को 14 भूखंडों के आवंटन में गड़बड़ी के आरोप हैं। अर्जी में एकल न्यायाधीश द्वारा सात फरवरी को दिए गए आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कथित घोटाले में लोकायुक्त पुलिस की जांच को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश पन वी अंजारीया और न्यायमूर्ति के वी अरविंद की पीठ ने 28 अप्रैल तक जवाब के लिए नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा, “प्रतिवादियों को 28 अप्रैल तक जवाब के लिए नोटिस जारी किया जाता है। चूंकि यह कहा गया है कि संबंधित मामले से जुड़ी अपील उस दिन सूचीबद्ध की गई हैं।” मूल याचिका इस वर्ष के प्रारंभ में खारिज करते हुए एकल न्यायाधीश ने कहा था कि लोकायुक्त की जांच में कोई पक्षपात या विसंगति प्रदर्शित नहीं हुई। अदालत ने कहा था, “लोकायुक्त की स्वतंत्रता संदिग्ध नहीं है।”

प्रयागराज : एक दंपति के सुरक्षा के अनुरोध वाले आवेदन पर निर्णय करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर प्रेम विवाह करने वाले जोड़े तब तक अधिकार के तौर पर पुलिस सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते, जब तक उनके जीवन और स्वतंत्रता को खतरा ना हो। अदालत ने कहा, एक उचित मामले में अदालत एक दंपति को सुरक्षा उपलब्ध करा सकती है, लेकिन कोई खतरा नहीं होने की सूरत में ऐसे दंपति को एक दूसरे का सहयोग करना और समाज के सामना करना सीखना होगा।”

केसरवानी और उसके पति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इस दंपति ने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी और समुराल वालों से उनके शारीपूर्ण वैवाहिक जीवन में दखल नहीं देने का निर्देश जारी करने की मांग की थी। अदालत ने याचिका में उल्लिखित बातों पर गौर करने के बाद पाया कि संबंधित पुलिस अधिकारियों को नहीं दिया है।



वैवाहिक जीवन में दखल नहीं देने का निर्देश जारी करने की मांग की थी। अदालत ने याचिका में उल्लिखित बातों पर गौर करने के बाद पाया कि संबंधित पुलिस अधिकारियों को नहीं दिया है।

विधानसभा चुनाव होने हैं। एक एआईसीसी पर्यवेक्षक और चार राज्य पर्यवेक्षकों समेत पांच सदस्यों वाली एक समिति गुजरात में पार्टी की 41 जिला इकाइयों (आठ शहरों समेत) में से प्रत्येक के लिए नए प्रमुखों की नियुक्ति की प्रक्रिया की देखरेख करेगी, जिसकी शुरुआत अरवल्ली जिले से होगी। अपने संबोधन में गांधी ने कार्यकर्ताओं से कई वादे किए जैसे कि जिला इकाइयों को अधिक शक्ति एवं धन उपलब्ध कराना, वरिष्ठ नेताओं-कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का आकलन करना, जमीनी स्तर पर सक्रिय पदाधिकारियों को बढ़ावा देना और उन नेताओं को हटाना जो या तो निष्क्रिय हैं या भाजपा के लिए काम कर रहे हैं।”

सोनिया, राहुल ने धोखे से ‘नेशनल हेराल्ड’ पर कब्जा किया, पैसे कमाए: हिमंत



इसकी कुल संपत्ति 2,000 करोड़ रुपये हो गई। इतना ही नहीं, यह धारा नौ के तहत आने वाली कंपनी है, जहां मुनाफा कमाने पर प्रतिबंध है, लेकिन वे मुनाफा कमा रहे थे।” उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी अक्सर उद्योगपति गौतम अडानी और पुंकेश अंबानी पर बहुत

महाराष्ट्र सरकार गटर की सफाई के लिए 100 रोबोट खरीदेगी: मंत्री शिरसाट

मुंबई : महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट का कहना है कि राज्य सरकार 27 नगर निगमों के लिए गटर की सफाई के वास्ते 100 रोबोट खरीदेगी। यह घोषणा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सफाई कार्यों का सामाजिक ऑडिट कराए जाने के बाद की गई है। ऑडिट में राज्य सरकार की सफाई कर्मचारियों की मौतों की समस्या से निपटने में विफलता को उजागर किया गया है। मुंबई, पुणे, परभणी, सतारा और शिरूर में केंद्र सरकार द्वारा किए गए सामाजिक ऑडिट ने महाराष्ट्र में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा में अधिकारियों और ठेकेदारों की गंभीर विफलताओं को उजागर किया है। ऑडिट के

बंगाल और सिक्किम में सेना का उच्च पर्वतीय अभियान ‘आर्मैक्स-24’ सफलतापूर्वक संपन्न

गंगटोक : भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी घने जंगलों से लेकर सिक्किम की दुर्गम, बर्फ से ढकी पहाड़ियों तक के इलाके में आयोजित उच्च पर्वतीय अभियान ‘आर्मैक्स-24’ को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह अभियान 22

दूरी पार की, जिसमें खड़ी चढ़ाइयों, अनिश्चित मौसम और बेहद मुश्किल रास्ते शामिल थे। अभियान का मार्ग बयान के अनुसार, सेना की विशेष रूप से चुनी गई 20 सदस्यीय टीम ने 18 दिनों तक लगातार कठिन परिस्थितियों में सफर तय किया। इस दौरान टीम ने 146 किलोमीटर की

पेड़ों की कटाई को लेकर तेलंगाना को न्यायालय की फटकार, 100 एकड़ वनभूमि बहाल करने की योजना देने को कहा

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास एक भूखंड पर पेड़ों को काटने के लिए जल्दबाजी में की गई कार्रवाई के वास्ते तेलंगाना सरकार को बुधवार को फटकार लगाई और निर्देश दिया कि यदि वह (राज्य सरकार) चाहती है कि उसके मुख्य सचिव को किसी भी गंभीर कार्रवाई से बचाया जाए तो वह कटाई से प्रभावित 100 एकड़ की वनभूमि पर फिर से पेड़ लगाने के लिए एक विशिष्ट योजना प्रस्तुत करे। पेड़ों को काटने की कांग्रेस सरकार की अत्यधिक जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह (अदालत) पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय की पहली चिंता पर्यावरण की बहाली है। पीठ ने यह भी कहा कि कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में इस भूमि पर



एक भी पेड़ अब नहीं काटा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति गवई ने तेलंगाना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा, यदि आप चाहते हैं कि आपके मुख्य सचिव या सचिवों को किसी भी कठोर कार्रवाई से बचाया जाए, तो आपको एक योजना बनानी होगी कि आप उस 100 एकड़ भूमि पर पेड़ कैसे लगाएंगे। पीठ ने कहा कि अपने कदम को उचित ठहराने के बजाय, राज्य सरकार के लिए बेहतर तरीका यह होगा कि वह वृक्ष आवरण को

उतराखंड में देश की सबसे लंबी सुरंग के निर्माण की सफलता के गवाह बने वैष्णव



जनासू (उत्तराखंड) : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बुधवार को उत्तराखंड के जनासू में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग के निर्माण में मिली सफलता के गवाह बने। एक बोरिंग मशीन ने चट्टान की आखिरी परत को तोड़कर दूसरी तरफ निकलकर सफलता हासिल की, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वैष्णव सुरंग में लगभग 3.5 किलोमीटर तक अंदर गए। देवप्रयाग और जनासू के बीच 14.57 किलोमीटर लंबी सुरंग संख्या-8 उत्तराखंड में महत्वाकांक्षी 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। वैष्णव ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया, क्योंकि यह सफलता 16 अप्रैल को मिली, जिस दिन 1853 में भारत में रेल सेवा शुरू हुई थी। पूरी परियोजना की

भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘डस्टलिक-6’ पुणे में शुरू



नयी दिल्ली : भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच एक संयुक्त अभ्यास बुधवार को पुणे में शुरू हुआ जिसका उद्देश्य अंतर-संचालन क्षमता विकसित करना और एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा करने से संबंधित आतंकवादी कार्रवाई का जवाब देना है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘डस्टलिक’ का छठा संस्करण 16-28 अप्रैल तक महाराष्ट्र के पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नाट, ऑपैंध में आयोजित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 60 सैन्यकर्मियों की भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व जाट रेजिमेंट और

भारत की वायु गुणवत्ता डब्ल्यूएचओ मानकों से काफी पीछे, एलपीजी सब्सिडी योजना बढ़ाने की जरूरत: निदेशक

नयी दिल्ली : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक अधिकारी ने कहा है कि भारत की वायु गुणवत्ता संयुक्त राष्ट्र के इस निकाय के मानकों से काफी कम है और देश की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी अब भी बायोमास ईंधन पर निर्भर है, जिसके कारण हर साल लोगों की मौत होती हैं। ‘पीटीआई वीडियो’ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में विश्व स्वास्थ्य संगठन में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉ. मारिया नीरा ने भारतीय अधिकारियों से मौजूदा कार्यक्रमों को, विशेष रूप से उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया जो खाना पकाने के लिए बायोमास ईंधन के उपयोग से घरों के भीतर होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से हैं। नीरा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से

हैं।” विश्व स्वास्थ्य संगठन की अधिकारी ने कहा कि आदर्श स्थिति यह होगी कि स्वच्छ ऊर्जा और नवीकरणीय गैर-प्रदूषक स्रोतों की ओर तुरंत कदम बढ़ाए जाएं, लेकिन नीति में निष्पक्षता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “हम मानते हैं कि एक निष्पक्ष बदलाव होना चाहिए, खासकर उन सबसे कमजोर लोगों के लिए जो वर्तमान में प्रदूषणकारी स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं। ऊर्जा के बेहतर स्रोतों के माध्यम से इस बदलाव में एलपीजी, बायोगैस, इथेनॉल तक पहुंच शामिल होगी, जो लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए बदलाव सुनिश्चित कर सकती हैं।” नीरा ने कहा कि वायु प्रदूषण गैर-संचारी रोगों या एनसीडी का प्रमुख कारण है, जो सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव का विषय होगा।

